मोदी की 'ईमानदारी'

विकिलीक्स के केबल की असलियत

आशीष मेहता

बहुत समय पहले 2007 में जब कुछ लोग ही नरेन्द्र मोदी के उज्जवल भविष्य को देख रहे थे, तब उन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के वक्त एक मजेदार जुमले का इस्तेमाल किया था - 'हूं खतो नथी अने खावा देतो नथी' (न तो मैं घूस खाता हूं और न ही खाने देता हूं)। आपने भी हर ओर उनके फोटो और इस स्लोगन वाले पोस्टर व होर्डिंग देखे होंगे। चुनावी अभियान के दौरान किए जाने वाले दावों के विपरीत यह भरोसेमंद लगा। कम से कम, एकमात्र विरोधी पार्टी कांग्रेस के पास पलटवार का कोई रास्ता नहीं था। घटनाओं से भरपूर रहे वर्ष 2002 में विपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री अमरसिंह चौधरी जनता के बीच कहा करते थे कि बेशक, मोदी भ्रष्ट नहीं हैं। पूर्व राजनीतिज्ञ यह इस सुर में बोलते थे कि 'एक अपवाद छोड़कर इस व्यक्ति में सौ खामियां हैं।'

राजकोट से एक कांग्रेसी राजनीतिज्ञ मनोहरसिंह जडेजा 2006 में इसी पार्टी लाइन को एक अमेरिकी राजनयिक के लिए दोहराते थे। बातचीत को एक गोपनीय राजनयिक ज्ञापन से हथियाया गया होगा और ज्ञापन को विकिलीक्स द्वारा लीक किया गया होगा। लिहाजा, मार्च 2011 में जब 'हिंदू' ने 'इंडिया केबल्स' प्रकाशित किया, इस शीर्षक ने मोदी की 'इन्क्रप्टिबिलटी' (भ्रष्ट न होने का गुण) पर प्रकाश डाला। मोदी के बारे में यह बात कह कौन रहा था? अपने ब्लॉग पर मोदी ने इसके अमेरिका से आने की अटकल लगाई। उनके ब्लॉग (http://www.narendramodi.in/i-am-glad-that-merica-admits-modi-is-incorruptible-hon%E2%80%99ble-cm/) के अनुसार उन्होंने कहा, 'विकिलीक्स केबल्स सही हैं। यह जानकर मुझे खुशी हुई कि अमेरिका मानता है कि मोदी को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता।' मौजूदा अभियान में मोदी के कुछ प्रशंसकों ने मतदाताओं को महान नेता के गुण याद दिलाने चाहे और इस तरह यह ट्वीट सामने आया कि कोई और नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ सचेतक विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे स्वयं कहते हैं कि मोदी को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता।

असांजे की एक फोटो व उनके जैसे दिखने वाले हस्ताक्षर के बीच ट्वीट में यह पंक्ति चलती है - 'अमेरिका मोदी से डरता है, क्योंकि वे जानते हैं कि मोदी को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता।' इस ट्वीट को लेकर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बीच कुछ प्रहसन भी हुआ कि असांजे ने कभी भी इस तरह का कुछ नहीं

कहा। जिस पर भाजपा प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी का जवाब था कि हमें असांजे के प्रमाण-पत्र की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि तब मोदी ने इसकी ढींग क्यों हांकी।

राजनीति में अन्य सब चीजों की तरह ही विकिलीक्स की विषय वस्तु पर भी प्रतिक्रिया के दो पक्ष हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आप किस के लिए काम कर रहे हैं। जब सामग्री आपके पसंदीदा नेता के पक्ष में हो, तो आप कह सकते हैं कि अब तो अमेरिका या विकिलीक्स (या जानकारी का वास्तविक स्रोत) भी ऐसा कहता है। यह मोदी का परिदृश्य है। जब सामग्री जोखिम भरी हो, तो आप कह सकते हैं कि यह आधारहीन है, यह तो बस एक धारणाभर है। यह अरुण जेटली का परिदृश्य है। भाजपा नेता को हिन्दू राष्ट्रवाद कहकर उद्धृत किया गया था जिसे संघ परिवार के बाहर हर कोई जानता है - एक अवसरवादी मुद्दा।

लेकिन सिर्फ 'धर्मनिरपेक्ष' हिन्दू समाचार-पत्र की रिपोर्ट्स के आधार पर ही एक या दूसरी तरह की प्रतिक्रिया देने से पहले इस केबल को पूरा पढ़ना ज्यादा विवेकपूर्ण रहेगा।

यहां उस केबल की सामग्री है जिसने कुछ कारणवश हिन्दू में प्रकाशित रिपोर्ट को 'ईमानदार मोदी' नहीं बताया। (हिन्दू के सौजन्य से मौलिक सामग्री इस वेब पेज पर पढ़ी जा सकती है http://www.thehindu.com/news/the-india-cables/the-cables/article1559806.ece)

'उन्होंने गुजरात के जनजीवन में भ्रष्टाचार घटाने वाले स्वच्छ राजनेता की छवि सफलतापूर्वक तैयार कर ली है। हालांकि, इस बात पर मतभेद है कि असल में मोदी कितने निष्कलंक और ईमानदार हैं।' इस तरह अमेरिका, विकिलीक्स या असांजे मोदी के समर्थक नहीं हैं, मोदी ही मोदी के समर्थन में हैं।

फिर भी, 'हमारे सभी वार्ताकार स्वीकारते हैं कि मोदी भारत के कई निर्वाचित अधिकारियों से अलग ऐसे शालीन व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने या अपने परिवार को संपन्न बनाने के लिए अपने पद का इस्तेमाल नहीं किया। कई संपर्क सूत्रों का भी कहना है कि उन्होंने नौकरशाही के मध्य और निचले स्तर पर राज्य प्रशासन के भ्रष्टाचार को साफ कर दिया है। हालांकि, कई लोग हमें बताते हैं कि बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार अब भी आम है।' अब आता है वह सारगर्भित विषय जिसमें (न्यूनाधिक) 'मोदी भ्रष्ट नहीं हो सकते' पंक्ति जितना ही सत्य है। 'पत्रकार जावेद रहमतुल्ला ने दावा किया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने जामनगर में अपनी रिफाइनरी का विस्तार करने की अनुमति के लिए ढेर सारी रिश्वत दी। रहमतुल्ला ने दावा किया कि पैसा मोदी या किसी और व्यक्ति के पास नहीं, भाजपा के खजाने में गया। अन्य संपर्कों से हमें पता चला कि गुजरात में व्यापार का पैसा भाजपा को जाता है, लेकिन किसी का भी उल्लेख नहीं किया गया था। हम रहमतुल्ला के दावे को सत्यापित करने में असमर्थ हैं।'

अगर कुछ इंतजार करें तो कोई प्रशंसक ट्वीट करेगा - मुकेश अंबानी का कहना है, मोदी को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता है। ■

ashishm@governancenow.com

वायदों का बड़ा बाजार

आलोक मेहता

चुनाव अभियानों के दौरान घोषणा-पत्रों या पार्टियों की प्रचार सामग्री में यह दावा अतिश्योक्तिपूर्ण लगता है कि पिछले 65 वर्षों में भारत बिल्कुल बर्बाद हो गया, भ्रष्टाचार के रसातल में डूब गया और आज भी देश गुलामी जैसी स्थिति में है। ये बातें इसलिए अनुचित लगती हैं कि 65 वर्षों के दौरान कांग्रेस ही नहीं अन्य प्रभावशाली राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तरों पर सत्ता संभाली है तथा गड़बड़ियों से अधिक बहुत अच्छे काम भी किये हैं। संचार क्रांति से लेकर परमाणु परीक्षणों तक में सबकी भूमिका रही है। समाजवादी या उदारवादी आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में सबकी भागीदारी रही है।

'प्राण जाये, पर वचन न जाये', जैसी पंक्तियां भारतीय समाज में श्रद्धा से याद की जाती हैं। लोकतंत्र में 'राम राज्य' का आदर्श गांधीवादियों, नेहरूवादियों, जेपी-लोहियावादियों, संघ-जनसंघ से लेकर अटल-मोदीवादियों की ओर से निरंतर रखा जा रहा है। दावा अन्ना हजारे के पूर्व शिष्य केजरीवाल कंपनी भी करती है, लेकिन उनकी गाइड बुक में राम राज्य से भी किसी अति काल्पनिक स्वर्ग राज्य के दर्शन होते हैं। इसलिए उनके नव वचनों की चर्चा उचित नहीं होगी। वचन यानी वायदा। राजनीतिक जीवन से अधिक महत्व देश के हजारों गांवों से महानगरों और कुछ हद तक दुनिया को जोड़ने वाले अनाज मंडियों तक के वायदा बाजार का रहा है। इसके उतार-चढ़ाव से लाखों-करोड़ों की जिंदगी-अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है। फिर भी इस समय राजनीतिक वायदों के बाजार भाव की चर्चा भारत ही नहीं ब्रिटेन, अमेरिका, चीन, दुबई और अफ्रीका तक है। इस लोक सभा चुनाव के बाद सचमुच क्या कोई सामाजिक-आर्थिक क्रांति हो जाएगी? कुछ समय पहले एक फिल्म बनी थी - 'तारे जमीन पर।' लेकिन हमारे राजनेताओं ने चुनावी वायदा-बाजार में 'चांद-तारे-सूरज जमीन पर' उतारने जैसे लुभावने वायदों के लंबे-चौड़े दस्तावेज जारी कर दिए हैं। वायदों और नारों के प्रचार पर लाखों नहीं, कुछ हजार करोड़ रुपए खर्च किये जा चुके हैं। निश्चित रूप से ये दस्तावेज ऐतिहासिक हो जाते हैं। जनता कुछ वायदे याद रखती है, तो बहुत सारे वायदे भूल जाती है। भारतीय अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुरूप सत्ताधारियों के प्रति उदार और क्षमावान रहते हैं। वहीं लोकतंत्र में अधिक धूर्तता और छलावा सहने के बाद वोट के जरिये सबक भी सिखला देती है।

ऐसी स्थिति में चुनाव अभियानों के दौरान घोषणा-पत्रों या पार्टियों की प्रचार सामग्री में यह दावा अतिश्योक्तिपूर्ण लगता है कि पिछले 65 वर्षों में भारत बिल्कुल बर्बाद हो गया, भ्रष्टाचार के रसातल में डूब गया और आज भी देश गुलामी जैसी स्थिति में है। ये बातें इसलिए अनुचित लगती हैं कि 65 वर्षों के दौरान कांग्रेस ही नहीं अन्य प्रभावशाली राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तरों पर सत्ता संभाली है तथा गड़बड़ियों से अधिक बहुत अच्छे काम भी किये हैं। संचार क्रांति से लेकर परमाणु परीक्षणों तक में सबकी भूमिका रही है। समाजवादी या उदारवादी आर्थिक नीतियों के क्रियान्वयन में सबकी भागीदारी रही है। गैर कांग्रेसी सरकारों में मोरारजी देसाई, चौ. चरणसिंह, वीपी सिंह, इंदर कुमार गुजराल से भी कई कदम आगे अटल बिहारी वाजपेयी के करीब 6 वर्षों के सत्ता काल को क्या बिल्कुल नजर अंदाज किया जा सकता है। पिछले 10 वर्षों के दौरान गुजरात ही नहीं म.प्र., छत्तीसगढ़, बिहार से लेकर केरल तथा पूर्वोत्तर राज्यों तक विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास हुआ है। यों गरीबी, गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अब भी बड़े पैमाने पर प्रयास करने होंगे, लेकिन ऐसा दावा भी शायद कोई नहीं कर सकता कि बस इस लोक सभा चुनाव के बाद हर भारतीय परिवार को एक घर, नल का शुद्ध पानी, संजीवनी बूटी की तरह चमत्कारिक चिकित्सा सुविधा और करोड़ों को रोजगार मिल जाएगा। बाबा रामदेव तो अपनी 'राजनीतिक योग' सभाओं में कांग्रेस के सत्ता से हटने के बाद नई सरकार आने पर विदेशों से अरबों रुपयों का काला धन लाकर हर भारतवासी को करोड़पति बन सकने का सपना भी दिखा रहे हैं।

जहां तक वायदों की बात है - महिलाओं के लिए सर्वाधिक सम्मान की बात करने वाली शक्तिशाली राजनीतिक दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी अब तक एकमत और दृढ़ता के साथ संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित नहीं कर पाईं। इसी तरह अयोध्या के श्रीराम अब भी भव्य मंदिर के बजाय तंबू की शरण में दर्शन दे रहे हैं। जबकि भाजपा अयोध्या के नारे से सत्ता के शिखर तक पहुंची थी। इस बार उसने फिर वही वायदा अपने घोषणा-पत्र के अंतिम सूत्र में बहुत सावधानीपूर्वक रखा है। यदि नेताओं को याद हो तो 'रोटी-कपड़ा-मकान' का वायदा और नारा कांग्रेस की तरह भाजपा का भी वायदा 20 बरस पुराना है। पार्टियों के घोषणा-पत्र 20 पृष्ठों के हों अथवा 50 पृष्ठों के - चुनाव के बाद यदि आप पार्टी के स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं से किसी 'संकल्प' के बारे में जानना चाहेंगे, तो संभवतः उनके पास घोषणा-पत्र की प्रति भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। घोषणा-पत्र चुनावी हो सकता है, लेकिन सबसे पुरानी कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में आपको आधुनिक भारत के निर्माता जवाहरलाल नेहरू तथा इंदिरा गांधी के ऐतिहासिक भाषणों के संकलन भी उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। शताब्दी वर्ष या 125 वर्ष पूरे होने पर निकाली गई कांग्रेस इतिहास की पुस्तकें भी कहीं पेपरबैक संस्करण की तरह कम दामों पर उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से अटलबिहारी वाजपेयी तक के विचारों की पुस्तकें निजी प्रकाशकों के माध्यम से महंगे दामों पर पुस्तकालयों तक पहुंच सकी हैं।

बहरहाल, इस चुनाव में भी कांग्रेस, भाजपा, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जद(यू), बीजू जनता दल, अन्ना द्रमुक या द्रमुक, तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां और नवोदित आम आदमी पार्टी ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कृषि, उद्योग-व्यापार, विज्ञान सहित हर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी लाभ जनता को पहुंचाने के वायदे घोषणा-पत्रों में किये हैं। लेकिन इन सबके लिए वित्तीय व्यवस्था कहां से होगी? क्या कोई एक पार्टी सरकार बना सकेगी? यदि नहीं तो गठबंधन के सहयोगी दल किन मुद्दों और क्षेत्रों पर प्राथमिकता में सहयोग देंगे? समान नागरिक संहिता जैसे प्रावधान के लिए संविधान में संशोधन लाने लायक बहुमत क्या भाजपा को मिल सकेगा? इसी तरह महिला आरक्षण तथा हर नागरिक को चिकित्सा के अधिकार का कानून कांग्रेस अपने बल पर दिला सकेगी? अपना विदेशी पूंजी निवेश तथा बड़े औद्योगिक घरानों पर नियंत्रण रखकर कम्युनिस्ट पार्टियां एवं आम आदमी पार्टी क्या आर्थिक प्रगति कर सकती हैं? दिवास्वप्नों के बजाय राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता की तरह वायदों के कारोबार में आत्म नियंत्रण क्यों नहीं कर सकते हैं? भोली-भाली जनता को वोट डालने के लिए प्रेरित करने के साथ अपनी कमजोरियां, मजबूरियां बताना पारदर्शी व्यवस्था का स्वागत योग्य कदम क्यों नहीं हो सकता है? चुनावी यज्ञ की आहुतियां तो शुरू हो चुकी हैं। घोषणा-पत्रों से आगे बढ़कर सरकार का गठन होने पर तो कम से कम एक प्रामाणिक व्यावहारिक वचनों का श्वेत-श्याम-नीला-पीला दस्तावेज जारी कर पांच साल में दशा-दिशा बदलने के सूत्र जनता के सामने रखे जा सकते हैं।

alokmehta7@hotmail.com